

सप्लाई की कमी से रिकॉर्ड ऊंचाई को छू सकता है रबड़ इंपोर्ट

केरल में आई भारी बारिश से रबड़ उत्पादन बुरी तरह प्रभावित, टायर कंपनियों के सामने इंपोर्ट के अलावा दूसरा विकल्प नहीं

कृष्णकुमार पी के कोच्चि |

रुपये में भारी गिरावट के बावजूद नेचुरल रबड़ का इंपोर्ट इस साल नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है क्योंकि घरेलू मार्केट में इसकी सप्लाई में किल्लत देखने को मिल रही है। देश में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य केरल में मई के बाद आई भारी बारिश से रबड़ का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके चलते टायर कंपनियों के पास रबड़ के इंपोर्ट के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है।

रबड़ बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच 172,000 टन उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 14 पसैंट कम है। वहीं इसके मुकाबले इसी अवधि में रबड़ की खपत 15 पसैंट बढ़कर 408,500 टन हो गई है। ऑटोमेटिव टायर मैनुफैक्चरर एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल राजीव बुधराजा ने

- अप्रैल-जुलाई 2018 में 172,000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 14% कम
- इसके मुकाबले इसी अवधि में रबड़ की खपत 15% बढ़कर 408,500 टन हो गई है

बताया, 'हमें लगता है कि इंपोर्ट 5 लाख टन को पार कर जाएगा और यहां तक कि यह इस साल 6 लाख टन के करीब भी पहुंच सकता है।' पिछले साल 4,69,433 टन का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ था।

आम तौर पर टायर इंडस्ट्री इंपोर्ट के लिए लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है, लेकिन भारी बारिश और रुपये में गिरावट से खराब होती स्थिति में इस समय यह

संभव नहीं है। बुधराजा ने बताया, 'इंडस्ट्री को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पॉट बेसिस पर खरीदना पड़ रहा है। इससे लागत बढ़ गई है।' चूंकि सिंथेटिक रबड़, स्टील टायर कॉर्ड, रबड़ केमिकल्स जैसे ज्यादातर दूसरे रॉ मैटेरियल भी इंपोर्ट किए जाते हैं, ऐसे में भी टायर कंपनियां इस साल घाटे के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'टायर कंपनियों की इनकम में इस साल कमी आएगी।

इस बीच, रबड़ का उत्पादन करने वाले किसान एक अंतराल के बाद फिर आक्रामक रूप से रबड़ टैपिंग कर रहे हैं क्योंकि इस समय मार्केट में उन्हें इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। RSS4 शीट रबड़ की कीमत मंगलवार को 134 रुपये प्रति किलो थी। इंडियन रबड़ डीलर्स फेडरेशन के पूर्व प्रेसिडेंट जॉर्ज वली ने बताया, 'शुरुआती कुछ महीनों में प्रॉडक्शन में आई कमी की आने वाले महीनों में भरपाई की जा सकती है।

